

an>

Title: Need to restore Scheduled Tribe status to people belonging to Lohar caste in Bihar.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं सरकार से बिहार के लोहार जाति के 18-20 लाख लोगों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में बताना चाहता हूँ। लोहार जाति के लोग वर्ष 1931 से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करते रहे हैं। वर्ष 1976 में पारित एक्ट संख्या 108/1976 के आधार पर जो अनुसूचित जनजातियों की सूची बनी, उस सूची में एस.टी. श्रेणी में "लोहार" का नाम अंकित था और उस सूची के अनुसार लोहार जाति को एस.टी. (अनुसूचित जनजाति) का जाति प्रमाण-पत्र भी 1 जुलाई 2007 तक मिलता रहा। परंतु दिनांक 02 जुलाई, 2007 से लोहार समाज के हमारे ये भाई-बहन यू.पी.ए. सरकार के दौरान पारित एक्ट (48/2006) में उल्लिखित प्रावधानों के कारण अपने अनुसूचित जनजाति के दर्जे से वंचित होने की स्थिति में आ गए हैं। इस एक्ट में "लोहार" को अंग्रेजी स्टाईल में बदलकर ""लोहार"" (Lohar) कर दिया गया जबकि यह सर्वविदित है कि बिहार में ""लोहार"" नाम से कोई जाति है ही नहीं। पिछले 8 वर्षों से मूल आदिवासी ""लोहार"" जाति का संवैधानिक हक छीना जा रहा है और उनका संवैधानिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अपने अधिकार को पाने के लिए इस समाज के लोग दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश हैं। एस.टी. का जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने से ये लोग बिहार में न तो अति-पिछड़ा की श्रेणी में हैं और न ही एस.टी. की श्रेणी में हैं। इसी कारण से इन्हें कहीं भी आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा है। आरक्षण नहीं मिलने के कारण शिक्षा एवं योजनाएं पाने में "लोहार" जाति पिछड़ने लगी है और इनकी आर्थिक स्थिति बंद से बदतर होती जा रही है। सरकार की नज़र में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना हस्तक के कारण आज लोहार समाज के लोग दर-दर भटक रहे हैं। लोहार को अंग्रेजी में Lohar लिखा जा सकता है, लेकिन हिन्दी में लोहार ही होगा। जोकि संवैधानिक एवं न्यायोचित है। वर्षों से हो रहे इनके विरुद्ध अन्याय को समाप्त कर न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वर्ष 2006 में पारित एक्ट संख्या 48/2006 को निरस्त किया जाये और उनकी जगह एक्ट संख्या 108/1976 को प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की जाये ताकि हमारे "लोहार" समाज के लोगों को पूर्व की भांति एस.टी. का दर्जा प्राप्त हो सके।